

माननीय बी.सी.वर्मा और अशोक भान, जे जे, के समक्ष

हरबंस लाल और एक अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य- उत्तरदाता।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 15523।

11 फरवरी, 1992।

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 (1984 के हरियाणा अधिनियम 11 द्वारा यथा संशोधित) - धारा 2 (जे) (iv), 2 (1) और 2 (एफ) - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 366 (29-ए) - 46 वां संशोधन 1982 - प्रविष्टि 54 सूची-II, संविधान की सातवीं अनुसूची - भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 - : धारा 148-1984 संशोधन जिसमें बिक्री कर लगाने का प्रावधान है "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण" पर - डीमड बिक्री की अवधारणा - बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मामले (एआईआर 1989 एस.सी. 1371) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक रूप से वैध माने गए 46 वें संशोधन के बाद की गई बिक्री की विस्तारित परिभाषा) - किसी वस्तु के कब्जे की सुपुर्दगी और उसकी अभिरक्षा के बीच का अंतर - वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का प्रश्न एक तथ्य है जिसे प्रत्येक मामले में अनुबंध की शर्तों के संबंध में निर्धारित किया जाना है - टेंट हाउस का व्यवसाय - कुर्सियों, मेजों, क्रॉकरी, टेंट, कनाट आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं का हस्तांतरण 'वस्तुओं' के अर्थ के भीतर आता है और अधिकार का हस्तांतरण होता है और संशोधित कानून के तहत इनका उपयोग बिक्री कर के दायरे में आता है - निर्माण उद्देश्यों के लिए बिल्डरों/ठेकेदारों को शटरिंग की आपूर्ति करने का व्यवसाय - हस्तांतरण प्रतिफल के लिए है - हस्तांतरणकर्ता प्रभावी नियंत्रण में रहता है और इसलिए टर्नओवर पर कर के लिए बिक्री योग्य होगा - ऐसा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति एक "डीलर" है - बोन ड्राई प्यूरिफाइड एसिटिलीन गैस iv

सिलेंडरों का निर्माण और बिक्री - विशेष अवधि से अधिक सिलेंडरों का प्रतिधारण 1 रुपये प्रति दिन निरोध शुल्क का उत्तरदायी है। - सिलेंडरों में गैस की बिक्री और एक विशेष अवधि के बाद सिलेंडर का प्रतिधारण माल की परिभाषा के अंतर्गत आता है - चूंकि माल हस्तांतरित करने का अधिकार है, इसलिए ऐसी बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है - कंपनी के कर्मचारियों के परिवहन के लिए बसों को किराए पर लेने का व्यवसाय - जहां यह पाया जाता है कि वाहन का प्रभावी या सामान्य नियंत्रण मालिक द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवर के माध्यम से कंपनी के पास रहता है। किराए पर लेने वाली कंपनी द्वारा अपनी कस्टडी से परिभाषित बसों के कब्जे का अधिग्रहण और इसके परिणामस्वरूप ट्रांसपोर्टर के कब्जे का नुकसान - 'लेनदेन मूल्यवान प्रतिफल के लिए वाहन का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के माध्यम से एक "बिक्री" है और बिक्री कर के अधीन है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक 46वें संशोधन की वैधता का संबंध है, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि एआईआर 1989 एस.सी. 1371 में बरकरार रखा गया है। इसलिए, इन याचिकाओं में 46वें संशोधन की वैधता को दी गई चुनौती नकारात्मक है।

संविधान की प्रविष्टि 29ए में एक समावेशी परिभाषा शामिल है, जिसके दायरे में "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर" शामिल है। प्रविष्टि 54 समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर करों से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 366 के खंड 29-ए में दी गई विस्तारित परिभाषा, को "माल की बिक्री और खरीद" की परिभाषा के लिए सौंपा गया है, जो वास्तव में होना चाहिए, तो राज्य विधानमंडल को बिक्री कर के संबंध में राज्य कानून से संबंधित "खरीद या बिक्री" शब्द की प्रविष्टि 54 में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी जो राज्य का विषय है।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया गया कि यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती को माल के कब्जे की डिलीवरी उन आवश्यक सामग्रियों में से एक है जहां अंतरिती को माल के प्रभावी और सामान्य नियंत्रण में रखा जाता है जो कि केवल *अभिरक्षा* या लाइसेंस से अलग होता है। माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से एक तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले में अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके तहत माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण होने की बात कही गई है।

(पैरा 12)

अभिनिर्धारित किया गया कि एचजीएस अधिनियम, 1973 की धारा 2 (1) का नोट-2, मूल्यांकन प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं करता है कि वह ऊपर उल्लिखित नोट-2 में उल्लिखित वस्तुओं पर बिक्री कर लगाए, बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार रखने वाला अंतरिती है। नोट-2 (सुप्रा) केवल यह स्पष्ट करता है कि धारा 2(1) का उप-खंड (iv) जहां तक यह नोट-2 में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित है, 1 अप्रैल, 1987 से लागू होगा। हमारे विचार में नोट-2 (सुप्रा) केवल याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए है क्योंकि धारा 2 (जे) और (आई) में संशोधन जो 'खरीद' और 'बिक्री' को परिभाषित करता है, 1984 के हरियाणा अधिनियम 11 के आधार पर प्रभावी हुआ और याचिकाकर्ता उस तारीख से धारा 2 (1) के नोट -2 में उल्लिखित आइटम पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन इस तथ्य के लिए कि इसे 1 अप्रैल से लागू किया गया है, 1987 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा 1987।

(पैरा 13)

अभिनिर्धारित किया गया कि माल का कब्जा, जो शटरिंग है, को विचार के साथ उपयोग के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अंतरिती को हस्तांतरित किया जाता है। अंतरिती उस अवधि के दौरान शटरिंग के प्रभावी नियंत्रण में होता है जब वह उसके कब्जे में रहता है। शटरिंग का कब्जा याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण के दौरान उपयोग के लिए ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है और यह "बिक्री" शब्द की परिभाषा के भीतर

आएगा क्योंकि संशोधित माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होता है। किसी को उपयोग के लिए शटरिंग प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त राशि, बिक्री की राशि होगी और इसे उसके 'टर्नओवर' में शामिल किया जाएगा। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता "डीलर" हैं क्योंकि वे विचार के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार को स्थानांतरित करते हैं और इसे संशोधित परिभाषा के अनुसार अधिनियम के तहत बिक्री-कर के लिए अपरिहार्य बनाने के लिए उनके कुल "टर्नओवर" में शामिल किया जाएगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि ग्राहकों को सिलेंडरों के साथ गैस की आपूर्ति की जाती है और सिलेंडरों का उपयोग करने के अधिकार के लिए मूल्य कुल राशि में शामिल होता है जो गैस की आपूर्ति के लिए ग्राहकों से शुल्क लिया जाता है जो "माल" शब्द की परिभाषा के भीतर आता है जो बिक्री के अनुबंध के समझौते के तहत लागू होता है। उस अनुबंध में आगे एक शर्त निर्धारित की गई थी कि यदि सिलेंडर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किए जाते हैं, तो प्रति सिलेंडर 1 रुपये प्रति दिन का शुल्क लगाया जाएगा जो बिक्री की निरंतरता में होगा और इस प्रकार का कोई भी पैसा याचिकाकर्ता के 'टर्नओवर' में शामिल किया जाएगा क्योंकि कंटेनर के रूप में सिलेंडर के साथ गैस की बिक्री और एक विशेष अवधि के बाद सिलेंडर का प्रतिधारण "माल" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। चूंकि इसमें माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण शामिल था, इसलिए उस पर लगाए गए किसी भी शुल्क को याचिकाकर्ता के कुल 'टर्नओवर' में शामिल किया जाएगा।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया गया कि, कि हमें नहीं लगता है, यह माना जा सकता है कि समझौते को निष्पादित करने के बाद वाहन का प्रभावी नियंत्रण उसके मालिक के पास रहता है। आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड द्वारा अपनी अभिरक्षा से अलग बसों के कब्जे का अधिग्रहण किया गया है और जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, बसों के कब्जे का हस्तांतरण होता है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता द्वारा अधिकार का अधिग्रहण किया जाता है और

हस्तांतरणकर्ता द्वारा इसे खो दिया जाता है। करार अनुबंध पी/एल के विभिन्न खंडों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बसों का प्रभावी कब्जा और नियंत्रण उपभोक्ताओं को जाता है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यह शब्द के विस्तारित अर्थ के भीतर 'बिक्री' का मामला है क्योंकि मूल्यवान विचार के लिए वाहन का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया गया था और बिक्री-कर अपरिहार्य है।

(पैरा 17)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -

- (क) परमादेश की रिट या कोई अन्य रिट या निदेश जिससे प्रतिवादी को टेंट लगाने की सेवा प्रदान करने के व्यावसायिक लेन-देन पर बिक्री-कर न लगाने का निदेश दिया जाए, क्योंकि टेंट को किराए पर देने से टेंट डीलर किसी भी तरह से बिक्री के लेन-देन को प्रभावित नहीं करते हैं; और
- (ख) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2(जे) (iv) और धारा 2(1) (iv) के उपबंधों को अवैध, असंवैधानिक और हरियाणा विधानमंडल की शक्तियों के विरुद्ध घोषित किया जाए;
- (ग) प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है जो उसे हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1973 की धारा 2(जे) (iv) और 2(1) (iv) के उपबंधों को लागू करने से रोकती हो; या
- (घ) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझा जाए, याचिकाकर्ता नंबर 1 और अन्य टेंट डीलरों के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ जारी किया जा सकता है;

(ड) इस माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत का निदेश दिया जाए जिससे प्रतिवादी को हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1973 की धारा 2(जे) (iv) और धारा 2(1) (iv) के उपबंधों को लागू न करने और हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम 1973 के उक्त उपबंधों के आधार पर मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने का निदेश दिया जा सके;

(च) प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस देने से छुटकारा दिया जा सकता है;

(छ) न्यायिक कागजातों/याचिका पत्रों पर रिट याचिका दायर करने से छूट दी जा सकती है क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हैं। याचिका सनलिट-बॉन्ड पेपर्स पर टाइप की गई है।

(ज) कि याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से के.बी. भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मिस वरुणा भंडारी और प्रदीप भंडारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए डी.डी.वासुदेव, डी.ए.जी, हरियाणा

निर्णय

**अशोक भान, जे।**

(1) यह निर्णय 1988 की सिविल रिट याचिकाओं संख्या 11860, 11861 और 1989 की 148, 12953, 13401, 14340, 15523 का निपटारा करेगा। इन याचिकाओं में उठाया गया कानून का प्रश्न हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (1984 के हरियाणा अधिनियम 11 द्वारा संशोधित) की धारा 2 (जे) और (1) के उप-खंड (iv) की संवैधानिक वैधता के बारे में है, जहां तक यह "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण" पर बिक्री-कर लगाने का प्रावधान करता है।

(2) इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता इमारतों के निर्माण के उद्देश्य से बिल्डरों/ठेकेदारों को टेंट, कनात, क्रॉकरी, बर्तन, फर्नीचर देने, शटरिंग देने, वापसी योग्य आधार पर सिलेंडर और सिलेंडर में गैस की आपूर्ति करने और याचिकाकर्ताओं से संबंधित बसों को तीसरे पक्ष को किराए पर देने का व्यवसाय कर रहे हैं। याचिकाएं या तो प्रस्तावित कर लगाने के लिए बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करने पर दायर की गई हैं या जहां मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक आकलन तैयार किए गए हैं और याचिकाकर्ताओं ने अपील में मूल्यांकन आदेशों को चुनौती देने के बजाय भारत के संविधान के 46 वें संशोधन जो 2 फरवरी, 1983 से लागू हुआ, की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की हैं और साथ में हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (जे) और (1) के उप-खंड (iv) की संवैधानिक वैधता को चुनौती (इसके बाद एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 के रूप में संदर्भित) दी। हम प्रत्येक मामले के तथ्यों से अलग से निपटने से पहले एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 और संविधान के 46 वें संशोधन के विभिन्न प्रावधानों की वैधता और संवैधानिक वैधता से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

(3) वर्ष 1984 में हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1984 के हरियाणा अधिनियम 11 द्वारा) के संशोधन पर प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का एक संक्षिप्त इतिहास, पार्टियों के तर्कों की सराहना करने के लिए इस स्तर पर निर्धारित किया जाना है। भारत के संविधान के प्रारंभ होने से पहले, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 48 द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों को बिक्री-कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 द्वारा संविधान द्वारा राज्य विधानमंडल को बिक्री-कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई थीं, जो मूल रूप से अधिनियमित इस प्रकार हैं:

"54 समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 92ए के प्रावधानों के अधीन"

भारत संघ से संबंधित सातवीं अनुसूची की सूची। में प्रविष्टि 92A इस प्रकार है: -

"92 ए. समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, जहां अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान ऐसी बिक्री या खरीद होती है"।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसरण में अधिनियमित बिक्री-कर और उसके बाद पारित बिक्री-कर से संबंधित कानूनों के लागू होने के बाद संविधान के लागू होने से इस आधार पर आगे बढ़ा कि विधायी सूचियों में प्रविष्टियों की व्यापक व्याख्या के दायरे के संबंध में नियम के संबंध में "माल की बिक्री" शब्द को व्यापक अर्थ दिया जाएगा। हालाँकि, मद्रास राज्य बनाम मैसर्स गैनन डंकरले एंड कंपनी (1) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "माल की बिक्री" का वही अर्थ है जो माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में है। यह निर्णय कार्य अनुबंधों से संबंधित है। बाद के निर्णयों की एक श्रृंखला में, इस मामले के पहलू से संबंधित कानून पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय जैसे *हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैसर्स एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया लिमिटेड (2)*, *सुश्री खारबुजा कुएर बनाम जंगबहादुर राय और अन्य (3)*, *मैसर्स विष्णव एजेंसियां (प्राइवेट लिमिटेड) वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य आदि (4)* और *मैसर्स नोथरन इंडिया कैटरर्स (इंडिया) बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल (5)* द्वारा विचार किया गया था। इन सभी निर्णयों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *गैनन डंकरले (सुप्रा)* के फैसले के आधार पर विभिन्न लेनदेन, जो वास्तव में, बिक्री के माध्यम से लेनदेन से मिलते जुलते हैं, को बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी नहीं माना। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप और किसी भी लेनदेन को राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर लगाने के अधीन करने के लिए, भारत के संविधान के 46वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया था।



(4) 46वें संशोधन को अपेक्षित संख्या में राज्य विधानसभाओं द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था और यह संशोधन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद 2 फरवरी, 1983 से प्रभावी हुआ। भारत के संविधान में 46वां संशोधन, जैसा कि संविधान के उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट है (46वां संशोधन अधिनियम, 1982), का उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना और विभिन्न तरीकों से करों से बचने की गुंजाइश को कम करना था; इसका उद्देश्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के प्रभाव को दूर करना भी था, जिन्हें इस फैसले के पहले भाग में संदर्भित किया गया था। यह अनुच्छेद 366 में एक नया खंड (29-ए) जोड़कर अनुच्छेद 366 में 'माल की बिक्री या खरीद पर कर' की परिभाषा को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करके किया गया था, जो इसके संशोधन के बाद प्रदान की गई परिभाषाओं से संबंधित है: -

"366. इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपे गए हैं, अर्थात्-

- (1) से (29) xx xx xx xx xx
- (29क) "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1131.

(2) ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1203.

(3) ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 449.

(4) ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1591.

(क) किसी भी माल में संपत्ति का नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए अनुबंध के अनुसरण में हस्तांतरण पर कर;

(ख) कार्य-अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर;

- (ग) किराया-खरीद पर माल की डिलीवरी पर कर या किस्तों के भुगतान की किसी भी प्रणाली;
- (घ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए (किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर";
- (ङ) किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल की आपूर्ति पर कर;
- (च) किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य तरीके से या किसी भी अन्य तरीके से, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (जो भी या नशीला नहीं है) की आपूर्ति पर कर, जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए है।

और किसी भी सामान के इस तरह के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री माना जाएगा जो हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति करते हैं और उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की खरीद करते हैं जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है।" संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा डाला गया।

(5) संविधान के अनुच्छेद 366 में प्रविष्टि 29ए के परिणामस्वरूप, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 का दायरा काफी हद तक बढ़ा दिया गया, जो "माल की बिक्री या खरीद पर कर" की परिभाषा प्रदान करता है। "। अनुच्छेद 366 में खंड 29ए में दी गई परिभाषा इसके दायरे में कई कानूनी लेकिन काल्पनिक बिक्री लाती है, जिसमें "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण" नकदी के लिए (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं), स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए कर शामिल है। "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण" के संबंध में 46वें संशोधन द्वारा "माल की

बिक्री और खरीद" पर परिभाषा में बदलाव के बाद, उप-खंड (iv) में दिए गए "खरीद" और "बिक्री" शब्दों की परिभाषा ) एच.जी.एस.टी. की धारा 2 के खंड (जे) और (1) के अधिनियम, 1973 (1984 के हरियाणा अधिनियम 11 द्वारा संशोधित) में भी संशोधन किया गया। एच.जी.एस.टी. की धारा 2 के खंड (जे) और (1) के उप-खंड (iv) अधिनियम, 1973, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

(2) परिभाषाएँ:- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो:-

(a) से (hh) xx xx

(जे) अपने सभी व्याकरणिक या आत्मीय अभिव्यक्तियों के साथ "खरीद" का अर्थ है नकद या स्थगित के लिए माल का भुगतान या स्थगित या बंधक, बंधक, प्रभार या प्रतिज्ञा के अलावा अन्य मूल्यवान विचार और इसमें शामिल हैं-

- (i) किसी अनुबंध के अनुसरण में, नकद आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी भी सामान में संपत्ति का हस्तांतरण;
- (ii) 18 अप्रैल, 1984 को या उसके बाद किए गए कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में);
- (iii) किराए की खरीद पर माल की डिलीवरी या किस्त द्वारा भुगतान की कोई प्रणाली;
- (iv) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं);

(v) किसी भी सेवा के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य तरीके से आपूर्ति करना, मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे वह मादक हो या नहीं), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए है; और इस तरह के हस्तांतरण, किसी भी सामान की आपूर्ति की डिलीवरी, उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की खरीद मानी जाएगी, जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है।

(ट) xxx xx xx xx

(I) "बिक्री" का अर्थ नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल में संपत्ति का हस्तांतरण है और इसमें शामिल हैं-

- (i) किसी अनुबंध के अनुसरण में, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी भी सामान में संपत्ति का हस्तांतरण;
- (ii) 18 अप्रैल, 1984 को या उसके बाद दर्ज किए गए कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में);
- (iii) किराए की खरीद पर माल की डिलीवरी या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी भी प्रणाली;
- (iv) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं);
- (v) आपूर्ति, किसी भी सेवा के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य तरीके से, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे वह मादक हो या नहीं), जहां ऐसी आपूर्ति

या सेवा, नकद के लिए है, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए है;

और किसी भी सामान के इस तरह के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री माना जाएगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरण वितरण या आपूर्ति करता है, जिसे इस तरह के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है, लेकिन इसमें बंधक, बंधक, उपबंध, शुल्क या प्रतिज्ञा शामिल नहीं है।

नोट-2 से धारा 2 (1) को 1987 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा जोड़ा गया था,

(6) जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में संकेत दिया गया है, इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने 46 वें संशोधन की वैधता के साथ-साथ एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2 (जे) और 2 (1) के उपखंड (iv) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जहाँ तक यह "नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं)" पर कर लगाने का प्रयास करता है। जहां तक 46वें संशोधन की वैधता का संबंध है, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा *बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य आदि* (6) बरकरार रखा गया है। इसलिए, इस याचिका में 46वें संशोधन की वैधता को चुनौती खारिज की जाती है।

(7) इस मामले में तय किया जाने वाला सवाल यह है कि क्या याचिका में निर्धारित स्थिति में अनुच्छेद 366 के खंड 29 ए और सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 और हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम में बाद के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए "किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण" होगा। "बिक्री" के मामले में, विक्रेता से खरीदार को स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण होता है, लेकिन संशोधित परिभाषा के अनुसार, जो प्रकृति द्वारा समावेशी है, जब भी किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का

उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया जाता है, तो वह भी 'बिक्री' के बराबर होगा। माल की बिक्री अधिनियम में परिभाषित बिक्री के अनुबंध और माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के बीच अंतर यह है कि माल की बिक्री के लेनदेन के मामले में, मालिक के स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित किए जाते हैं, जबकि उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के मामले में, माल में स्वामित्व अधिकार मालिक के पास रहते हैं। संपत्ति के मालिक के पास अधिकारों का एक बंडल है, अर्थात्; रखने का अधिकार, उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार, भोगने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार, नष्ट करने का अधिकार, अलग करने का, हस्तांतरित करने का अधिकार आदि। कानून में, संपत्ति का मालिक संपत्ति पर शुल्क लगा सकता है, इसे गिरवी रख सकता है या इसे पट्टे पर दे सकता है या इसे बेच सकता है। काल्पनिक कानून यह संभव बनाता है कि विभिन्न अधिकार और हित जैसे कि रखने का अधिकार, उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार, उपभोग का अधिकार, अलगाव या हस्तांतरण का अधिकार विभिन्न व्यक्तियों में निहित हो सकते हैं। संविधान में 46वें संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 366 में खंड 29-ए को शामिल करके और एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2(जे) और 2(1) में बदलाव करके, ऐसे अधिकारों में से एक यानी "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण" पर कर लगाने की मांग की गई है; दूसरे शब्दों में हम इन मामलों में "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण" और संशोधित प्रावधानों के माध्यम से कर लगाने की कानूनी अवधारणा से चिंतित हैं।

(8) प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों से निपटने से पहले, हम उस व्यापक चुनौती पर चर्चा करने का प्रस्ताव करते हैं जो विभिन्न मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील द्वारा रखी गई है जो सभी मामलों में सामान्य है।

(6) ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1371 (173 एस.टी.सी. 370)

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की पहली दलील यह है कि सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 में संशोधन के बिना राज्य विधानमंडल एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2 (जे) और (आई) में संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं था। हमें इस निवेदन में कोई दम नजर नहीं आता। संविधान का अनुच्छेद 366 उन परिभाषाओं से संबंधित है जिनके द्वारा संविधान में होने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को अर्थ सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 366 की प्रविष्टि 29ए एक समावेशी परिभाषा है जिसके दायरे में "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर" शामिल है। प्रविष्टि 54 समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर करों से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 366 के खंड 29-ए में दी गई विस्तारित परिभाषा को "वस्तुओं की बिक्री और खरीद" की परिभाषा को सौंपा गया है, जो वास्तव में होना चाहिए, तो सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 में संशोधन करना आवश्यक नहीं था ताकि राज्य विधानमंडल बिक्री-कर के संबंध में राज्य कानून से निपटने के दौरान "खरीद या बिक्री" शब्द की परिभाषा में संशोधन कर सके, जो राज्य का विषय है।

(10) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि भले ही एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (जे) और (आई) के खंड (iv) का संशोधन को वैध माना जाता है, फिर मौजूदा मामले में बिक्री का कोई तत्व नहीं था और याचिकाकर्ता केवल किराये का शुल्क ले रहे थे और स्थानांतरण माल के 'उपयोग' के अधिकार के उद्देश्य से नहीं था लेकिन प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क की प्रकृति भी वैसी ही थी। "किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण" उपनिधान की एक प्रजाति है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148, उपनिधान को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है: -

"148. " उपनिधान ", " उपनिधाता " और " उपनिहिती " को परिभाषित किया गया है। एक " उपनिधान " एक अनुबंध पर किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है, जिसे वे, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा या अन्यथा उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निपटान किया जाएगा। सामान पहुंचाने वाले व्यक्ति को उपनिधाता कहा जाता है। जिस व्यक्ति को वे वितरित किए जाते हैं, उसे " उपनिहिती " कहा जाता है।

इस प्रकार, उपनिधान में एक विशेष अवधि के लिए माल का हस्तांतरण होता है और उसके बाद माल को उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति को वापस किया जाना होता है। माल की डिलीवरी के बाद ही उपनिहिती कानूनी रूप से ऐसे सामान का अधिकारी बन जाता है और समय-समय पर भुगतान पर या जमानतदार को अन्य मूल्यवान विचार के खिलाफ माल के उपयोग का आनंद लेने का हकदार बन जाता है। उपनिधाता को प्रतिफल मिलता है जबकि उपनिहिती को माल का आनंद लेने का अधिकार मिलता है और यह केवल माल की डिलीवरी पर पूरा होता है। हस्तांतरणकर्ता किराए पर लिए गए माल का कब्जा प्राप्त करने के बाद ही उपयोग के अधिकार का प्रयोग करना शुरू करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास सामान है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह उस पर काल्पनिक या वास्तविक नियंत्रण में है और यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और कभी-कभी कानूनी निष्कर्ष निकालना पड़ता है। यह समझा जाना चाहिए कि जब किसी चल संपत्ति को किराये पर देना उसे उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के रूप में मानकर बिक्री माना जाएगा। वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है। ये तय किए गए मामले हाथ में विवाद पर प्रकाश डालते हैं। *राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कंपनी सर्कल, विशाखापत्तनम (7)*, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण उपनिधान की एक प्रजाति है और उस उद्देश्य के लिए, माल के कब्जे की डिलीवरी आवश्यक है। किसी वस्तु के कब्जे के विरुद्ध उसके कब्जे



की अभिरक्षा के बीच एक अंतर खींचा गया था। कब्जे की डिलीवरी के बीच सूक्ष्म अंतर को "रेंट-ए-कार" योजना के तहत टैक्सी कैब किराए पर लेने का उदाहरण लेकर सामने आया था, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किराए पर ली गई टैक्सी का उदाहरण लिया गया था। निम्नलिखित पैराग्राफ, उक्त निर्णय के सूक्ष्म अंतर को सामने लाने के लिए, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: –

"हस्तांतरण का सार संपत्ति के आर्थिक लाभों पर नियंत्रण का पारित होना है, जिसके परिणामस्वरूप एक इकाई में अधिकारों और अन्य संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है और उन्हें दूसरे में बनाया जाता है। "स्थानांतरण" शब्द का अर्थ लगाते समय स्थानांतरित की जाने वाली वस्तु पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण में आवश्यक रूप से हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरी को कब्जे का वितरण शामिल है। किसी वस्तु के कब्जे की सुपुर्दगी को उसकी अभिरक्षा से अलग किया जाना चाहिए। यह असामान्य बात नहीं है कि हस्तांतरी के पास माल है, जबकि हस्तांतरणकर्ता के पास उसकी अभिरक्षा है। जब "रेंट-ए-कार" योजना के तहत एक टैक्सी कैब किराए पर ली जाती है, और एक कैब प्रदान की जाती है, तो आमतौर पर ड्राइवर कैब के साथ वहां जाता है, ड्राइवर के पास कार की अभिरक्षा होगी, हालांकि किराए पर लेने वाले के पास कैब का कब्जा और प्रभावी नियंत्रण होगा। यह उस मामले के विपरीत हो सकता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक टैक्सी कार किराए पर ली जाती है। वहां चालक के पास अभिरक्षा के साथ-साथ कब्जा दोनों होगा; जो प्रदान किया जाता है वह किराए पर सेवा है। पहले मामले में, कैब पर किरायेदार (हस्तांतरी) का प्रभावी नियंत्रण होता है, जबकि बाद के मामले में इसकी कमी होती है। इस अंतर को इंगित करने के लिए हमारे पास कई उदाहरण हो सकते हैं।"

(7) 1990 एस.टी.सी. 182

(11) इस मामले में, लेनदेन को उतना असंगत नहीं माना गया था जितना कि मशीनरी का प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरणकर्ता के पास रखा गया था, न कि हस्तांतरी के पास। मॉडर्न डेकोरेटर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी मणिकोटला और अन्य (8), का एक और मामला (अदालत की अनुमति से उद्धृत किया गया था) जिसमें आवेदक 50 से अधिक वर्षों से डेकोरेटर के रूप में व्यवसाय कर रहा था। आवेदक के व्यवसाय में शामिल थे; अन्य बातों के साथ-साथ, बांस, साल बलिया, रस्सियों, तिरपालों, सजाने वाले कपड़े और अन्य सामग्रियों की सहायता से विभिन्न ग्राहकों द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर भूमि, धरती, सड़क, भवन, छत आदि पर पंडाल, बैरिकेड्स, चबूतरे आदि का निर्माण, निर्माण और स्थापना करना। निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, पंडालों, बैरिकेड्स, रोस्ट्रम या मंडपों को डेकोरेटर द्वारा अपने स्वयं के आदमी और श्रम के साथ ध्वस्त कर दिया गया था और सामग्री को आदेशों के अनुसार बाद में उपयोग के लिए आवेदक के गोदाम में वापस ले जाया गया था। आवेदक अपने ग्राहकों, कुर्सियों और मेज आदि को किराए पर भी देता है। यह माना गया कि आवेदक ने अपने ग्राहकों को सामग्री नहीं दी है। जहां तक पंडाल आदि के निर्माण का सवाल है, आवेदक ने कीमत के एवज में पंडालों का निर्माण किया और निर्दिष्ट अवधि के बाद इसे विघटित कर दिया और वस्तुओं को अपने गोदाम में हटा दिया; पंडालों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री स्थानांतरित नहीं की गई थी। पंडालों को खड़ा करने और बाद में इसका उपयोग करने के लेन-देन में हस्तांतरणकर्ता में माल का कोई शीर्षक पारित नहीं किया गया था और यही कारण है कि यह माना गया कि संशोधित परिभाषा के संदर्भ में यह "माल की बिक्री" नहीं है। हालांकि, विभिन्न अन्य वस्तुएं, जो डेकोरेटर अपने व्यापार के दौरान सौदा करते हैं, को अधिनियम के अर्थ के भीतर "माल" माना गया था और यह माना गया था कि वे संशोधन के अनुसार "बिक्री" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण का सारांश निम्नानुसार था :-

"हालांकि, हम इस सकारात्मक निष्कर्ष पर आना जरूरी नहीं समझते कि पंडाल 'सामान' है या नहीं। लेकिन, हमने पाया है कि ग्राहकों के कहने पर डेकोरेटर्स द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बनाए गए पंडालों को

किराए पर लेना, "बिक्री" के अर्थ में नहीं आ सकता है, इसलिए यह बिक्री कर के दायरे में नहीं आता है। यह तर्क कि जिन विभिन्न सामग्रियों से पंडाल बनाए जाते हैं, उनका किराया मूल्य हमारे विचार में "माल" है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह वह सामग्री नहीं है जिसे ग्राहकों द्वारा उपयोग के लिए स्थानांतरित किया जाता है। यह डेकोरेटर द्वारा प्रदान की गई सेवा की समग्रता है, अर्थात्, पंडालों का निर्माण, आदि जो हमारे विचार के लिए आता है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न अन्य वस्तुएं जो डेकोरेटर अपने व्यापार के दौरान अपने ग्राहकों को देती हैं, जैसे, टेबल, कुर्सियां आदि अधिनियम के अर्थ के भीतर "माल" हैं और वे संशोधित "बिक्री" की परिभाषा के भीतर आ सकते हैं।

12. परिस्थितियों में, आवेदन भाग में सफल होता है। प्रतिवादियों को बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 14 (1) और दिनांक 7 दिसंबर के व्यापार परिपत्र संख्या 2/84 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी 5 नवंबर, 1985 के नोटिस के अनुसरण में कोई भी प्रभाव डालने या कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए निषेध की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 1984 जारी किया गया और उत्तरदाताओं को सजाने के अपने व्यवसाय के संबंध में आवेदक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए पंडाल आदि के निर्माण के लिए कोई बिक्री-कर लेने से प्रतिबंधित किया गया। हालांकि, डेकोरेटर द्वारा ग्राहकों को किराए पर दी गई वस्तुओं की अन्य वस्तुएं "बिक्री" के अर्थ के भीतर आएंगी और यदि कारोबार कर योग्य सीमा से अधिक है तो कर का आकलन किया जा सकता है। उपरोक्त निर्देशों के साथ, मामले का निपटारा किया जाता है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।"

*बैंक ऑफ इंडिया बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, मध्य अनुभाग, कलकत्ता और अन्य (9), कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मुख्य रूप से "बिक्री" अभिव्यक्ति की विस्तारित परिभाषा के भीतर बैंक लॉकर के पट्टे को बैंक लॉकर की बिक्री के रूप में नहीं माना क्योंकि लॉकर को किराए पर लेने को लॉकर के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण नहीं माना जाता था, बल्कि इसके अलावा विभिन्न सेवाएं प्रदान करना था। इसके लिए मुख्य कारण यह दिया गया था कि*

बैंक ने कभी भी ग्राहक को लॉकर का वास्तविक कब्जा नहीं दिया। बैंक ने एक स्ट्रॉंग रूम बनाया था, डबल लॉकिंग सिस्टम के साथ सुरक्षा लॉकर के साथ एक स्टील कैबिनेट स्थापित किया था; एक चाबी ग्राहक को दी गई और दूसरी को बैंक द्वारा अपने पास रखा गया। लॉकर को तब तक संचालित नहीं किया जा सकता था जब तक कि लॉकर खोलने के लिए दोनों चाबियों का उपयोग नहीं किया जाता था। ग्राहक को केवल तभी तिजोरी में प्रवेश दिया गया जब बैंक ने इसकी अनुमति दी अधिकृत ग्राहकों को लॉकर का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, जो पहले से ही बैंक की पुस्तकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। यह माना गया था कि बैंक ने ग्राहक द्वारा देय किराए के लिए लॉकर में संग्रहीत सामान पर ग्रहणाधिकार रखा था। लॉकर की लीज पर टैक्स लगाने की विभाग की दलील खारिज कर दी गई। इसी तरह का दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (10) मामले में लिया गया था। । हालाँकि, इस मामले में लॉकर को किराये पर लेने को 'बिक्री' न मानने का मूल तत्व यह था कि उस सामान की डिलीवरी का अभाव था जिसे आवश्यक घटक माना जाता था। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 36जी के खंड 29-ए में उन मामलों का उल्लेख किया गया है, जहां संबंधित व्यक्ति को वितरित माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण होता था। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि परिभाषा उस लेन-देन को अपने दायरे में नहीं लेती है जो केवल किसी व्यक्ति को कब्जा सुरक्षित किए बिना सामान का उपयोग करने का लाइसेंस देता है; यह माना गया कि किराएदार को लॉकर के कब्जे की कोई डिलीवरी नहीं हुई थी और इसलिए, लेनदेन को "बिक्री" नहीं माना गया और इसलिए, बिक्री कर के दायरे में नहीं आया।

(8) 67 एस.टी.सी. 199

(9) (1988) 70 एस.टी.सी. 215

(12) ऊपर उल्लिखित मामले के कानून के अवलोकन से, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणी को माल के कब्जे का वितरण आवश्यक अवयवों में से एक है जहां हस्तांतरणी को माल के प्रभावी और सामान्य नियंत्रण में रखा जाता है जैसा कि केवल अभिरक्षा या उसी का उपयोग करने के लाइसेंस से अलग है। माल का उपयोग करने के

अधिकार का हस्तांतरण है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है जिसे प्रत्येक मामले में अनुबंध की शर्तों के संबंध में निर्धारित किया जाना है जिसके तहत माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण कहा जाता है। तथ्यों की इस पृष्ठभूमि में, हम प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में प्रत्येक मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह अधिक उपयुक्त होता, यदि इन तथ्यों को अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता क्योंकि इस न्यायालय को केवल उन तथ्यों से उत्पन्न कानून के सवालों को निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था क्योंकि कुछ मामलों में, मूल्यांकन कार्यवाही विभिन्न अधिकारियों के समक्ष लंबित है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील के जोर देने पर, हम इन सवालों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लंबे तर्कों को संबोधित किया गया था।

सी.डब्ल्यू.पी. 1989 की संख्या 143/14340 और 15523।

(13) इन मामलों में याचिकाकर्ता टेंट हाउस का व्यवसाय चला रहे हैं जिसमें ग्राहकों द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अपने स्वयं के नौकरों और परिवहन के माध्यम से टेंट स्थापित करके ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है। टेंट ग्राहकों के परिसर में लगाए जाते हैं और समारोह समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ताओं के कर्मचारियों द्वारा टेंट को याचिकाकर्ताओं के व्यावसायिक परिसर में वापस लाया जाता है; आगे कहा गया कि किसी भी स्तर पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा ग्राहकों को टेंट हस्तांतरित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता ग्राहकों को समारोह आयोजित करने के उद्देश्य से क्रॉकरी, बर्तन और फर्नीचर की आपूर्ति भी करते हैं। क्रॉकरी और फर्नीचर को याचिकाकर्ताओं के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के परिसर में भी ले जाया जाता है; याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्त किए गए वाहक मेहमानों को भोजन आदि परोसते हैं और समारोह समाप्त होने के बाद, उसे याचिकाकर्ताओं के व्यवसाय परिसर में वापस लाया जाता है; यह तर्क दिया गया था, कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ताओं द्वारा टेंट, क्रॉकरी, बर्तन, इम्प्यूटर नहीं बेचे गए थे। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उपयोग

किए गए टेंट, क्रॉकरी, बर्तन और फर्नीचर को बिक्री कर का भुगतान करने के बाद खरीदा गया था और इसलिए, याचिकाकर्ताओं से कोई बिक्री कर नहीं लिया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने माल का कब्जा या उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया था या और प्रतिफल केवल प्रदान की गई सेवाओं के लिए था। एक अन्य तर्क यह दिया गया था कि एच.जी.एस. अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (1) के नोट -2, जो निर्णय के पहले भाग में संदर्भित किया गया था, जो 1 अप्रैल, 1987 से लागू हुआ था, ने आकलन प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि वह बिक्री-कर वसूल करे, जहां तक यह माल से संबंधित है अर्थात् शटरिंग सामग्री (भवनों के निर्माण में इस्तेमाल) टेंट, कनात, छंदरी, क्रॉकरी, बर्तन, फर्नीचर आदि, इस तथ्य के बावजूद कि क्या सामान का कब्जा हस्तांतरणकर्ता से हस्तांतरी को हस्तांतरित किया गया था या नहीं, या क्या एच.जी.एस. अधिनियम, 1973 की धारा 2 (1) के उप-खंड (iv) द्वारा विचार किए गए माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण हुआ था या नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने व्यवसाय के दौरान ग्राहकों को कोई सामान हस्तांतरित नहीं किया और याचिकाकर्ताओं ने केवल प्रदान की गई सेवाओं के लिए किराए पर लेने का शुल्क लिया। दायर लिखित बयान में, यह कहा गया था कि राज्य विधायिका हरियाणा राज्य में माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के संदर्भ में, और इन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य विधानमंडल ने एच.जी.एस.टी. की धारा 2(जे) (iv) और 2(1) (iv) को अधिनियमित किया था। 2 फरवरी, 1983 से प्रभावी भारत के संविधान के 46वें संशोधन के माध्यम से शक्तियां प्रदान किए जाने और टेंट डीलरों द्वारा टेंट, कनाट और फर्नीचर आदि जैसे सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण से ग्राहकों से वसूले गए किराया प्रभारों पर कर लगाने के बाद 1 अप्रैल, 1984 से 1 अप्रैल, 1984 से एच.ए. 11 द्वारा इन खंडों को शामिल किया गया था। तथ्यों पर, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता ग्राहकों को किराए पर टेंट, कनाट, फर्नीचर आदि देने के व्यवसाय में लगे हुए हैं और इस प्रकार शुल्क एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2 (जे) और 2

(1) के उप-खंड (iv) के तहत 'बिक्री' के दायरे में आते हैं और कर के लिए उत्तरदायी हैं। नोट-2 के संबंध में, जिसे हरियाणा अधिनियम 10, 1987 द्वारा जोड़ा गया था, यह कहा गया था कि उक्त नोट में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में, कर 1 अप्रैल, 1987 से लागू हो जाते हैं, जबकि उप-खंड (बी और (v) संशोधन 2 फरवरी, 1983 से लागू हुआ जैसा कि नोट-1 से स्पष्ट है और नोट 1 और 2 केवल वे तारीखें देते हैं जिनसे धारा 2 का उपखंड (1) लागू हुआ और मूल्यांकन करने वाले प्राधिकारी तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र थे कि क्या किसी भी सामान के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण हुआ था, जिसका उल्लेख धारा 2 के खंड (1) के नोट -2 में मिलता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए टेंट, कांटा और अन्य सजावट सामग्री का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यदि पंडाल बनने के बाद ही ग्राहकों को उपयोग के लिए दिया जाता है तो यह एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2(डी) के अर्थ के तहत माल का हस्तांतरण नहीं हो सकता है जिसमें "माल" शब्द को परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर भी जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा टेंट, कनात और फर्नीचर ग्राहकों को दिए जाते हैं और ग्राहक उन्हें खड़ा करते हैं और टेंट के लिए किराया शुल्क का भुगतान करते हैं। कनात, छोलदारी क्रॉकरी आदि तो वही "माल" के अर्थ में आते हैं और इसके उपयोग के अधिकार का कोई भी हस्तांतरण बिक्री-कर के दायरे में आएगा। विभिन्न वस्तुओं जैसे कि कुर्सियाँ, मेज और क्रॉकरी आदि का हस्तांतरण, निश्चित रूप से, "माल" शब्द के अर्थ के अंतर्गत आएगा और उन वस्तुओं पर उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर लगेगा क्योंकि वह इसके अंतर्गत आएगा। "बिक्री" की परिभाषा में संशोधन किया गया। हम उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से सहमत हैं कि एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2(1) के नोट-2, उपरोक्त उल्लिखित नोट-2 में उल्लिखित वस्तुओं पर बिक्री-कर लगाने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को बाध्य नहीं करता है, तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना कि माल के उपयोग के अधिकार के साथ हस्तांतरिती को प्रभावी नियंत्रण के साथ कब्जे का हस्तांतरण होता है। नोट-2 (सुप्रा) केवल यह स्पष्ट करता है कि धारा 2(1) का उप-खंड (iv) जहां तक नोट-

2 में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित है, 1 अप्रैल, 1987 से प्रभावी होगा। हमारे विचार में नोट-2 (सुप्रा) केवल याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए है क्योंकि धारा 2(जे) और (1) में संशोधन जो 'खरीद' और 'बिक्री' को परिभाषित करता है, 1984 के हरियाणा अधिनियम 11 के आधार पर लागू हुआ और याचिकाकर्ता उस तिथि से धारा 2(1) के नोट-2 में उल्लिखित वस्तु पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन इस तथ्य के लिए कि इसे 1987 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा 1 अप्रैल, 1987 से लागू किया गया है।

सी.डब्ल्यू.पी. 1988 की संख्या 11860 और 11861।

**(14)** इन याचिकाओं में, याचिकाकर्ता इमारतों के निर्माण के उद्देश्य से बिल्डरों / ठेकेदारों को शटरिंग की आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं; याचिकाकर्ताओं द्वारा बिल्डरों/ठेकेदारों को आपूर्ति की जाने वाली शटर सभी चरणों में याचिकाकर्ताओं की संपत्ति बनी रहती है क्योंकि बिल्डरों/विरोधियों को शटरिंग के हस्तांतरण के लिए याचिकाकर्ताओं और ठेकेदारों के बीच कोई अनुबंध नहीं है; यह कि बिल्डरों/ठेकेदारों को शटरिंग की आपूर्ति के माध्यम से हस्तांतरण में संपत्ति का हस्तांतरण शामिल नहीं है; शटरिंग 10/12 बार उपयोग करने के बाद एक खराब होने वाली वस्तु है, यह उपयोग के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो जाता है और एक ही वस्तु पर बार-बार बिक्री-कर नहीं हो सकता है। धारा 2 के खंड (1) के नोट-2 की प्रयोज्यता के संबंध में अन्य दलीलें उसी प्रकृति की थीं जो टेंट आदि के मामले में थीं। लिखित बयान में जिन कानूनी बातों का खंडन किया गया है, वे भी उन्हीं शब्दों में थे जैसे टेंट आदि के मामले में थे। तथ्यों पर, यह कहा गया था कि शटरिंग "माल" शब्द के अर्थ के भीतर आएगी और उपयोग के अधिकार के साथ इसका हस्तांतरण कर के लिए अपरिहार्य होगा। हमें प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए वकील की दलील में दम नजर आता है। माल का कब्जा, जो शटरिंग है, को प्रतिफल के साथ उपयोग के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है। जब तक शटरिंग उसके कब्जे में रहती है तब तक स्थानांतरित व्यक्ति शटरिंग पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। शटरिंग का कब्जा याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण के दौरान उपयोग के लिए ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है और यह "बिक्री" शब्द



की परिभाषा के भीतर आएगा क्योंकि संशोधित माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होता है। किसी को उपयोग के लिए शटरिंग प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त **प्रतिफल** बिक्री की राशि होगी और इसे उसके 'टर्नओवर' में शामिल किया जाएगा। हमें याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की इस दलील में कोई आधार नहीं मिला कि याचिकाकर्ता एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 की धारा 2 (सी) में परिभाषित "डीलर" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता "डीलर" हैं क्योंकि वे **प्रतिफल** के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार को स्थानांतरित करते हैं और इसे संशोधित परिभाषा के अनुसार अधिनियम के तहत बिक्री-कर के लिए अपरिहार्य बनाने के लिए उनके कुल "टर्नओवर" में शामिल किया जाएगा।

*सी.डब्ल्यू.पी. 1989 का 12953।*

(15) इस मामले में, याचिकाकर्ता का फरीदाबाद में एक कारखाना है और वह हड्डी के सूखे शुद्ध एसिटिलीन गैस के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है, जिसके लिए उसने खुद को एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 1973 के तहत 'डीलर' के रूप में पंजीकृत कराया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने कारखाने में निर्मित गैस सिलेंडरों में भरी जाती है जिसे ग्राहकों, डीलरों, सरकारी विभागों को इस शर्त के साथ बेचा जाता है कि संयंत्र को चालू रखने के लिए सिलेंडर को याचिकाकर्ता को तुरंत वापस करना होगा क्योंकि सिलेंडरों में गैस भरने के लिए खाली सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, जैसे ही इसे संयंत्र से निर्मित किया जाता है और ग्राहकों द्वारा सिलेंडरों को रोके रखने से संयंत्र बंद हो जाएगा और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत में वृद्धि; स्थायी प्रकृति के महंगे कंटेनर होने के कारण गैस सिलेंडर को ग्राहकों द्वारा उनकी इच्छा से हिरासत में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, याचिकाकर्ता का उद्देश्य और हित उचित अवधि से अधिक समय तक गैस का उपयोग करने के बाद ग्राहकों को सिलेंडर की अनुमति नहीं देना है, जो कि 7 से 10 दिनों की है जो संयंत्र से ग्राहकों की दूरी पर निर्भर है; बिक्री के अनुबंध में एक शर्त यह है कि ग्राहक को भरे हुए गैस सिलेंडर के उपयोग के बाद याचिकाकर्ता की कंपनी को खाली सिलेंडर तुरंत वापस करना होगा, लेकिन 7 से 10 दिनों की अवधि से

अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर ग्राहक प्रति दिन 1 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से नुकसान या दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; यह आगे कहा गया है कि बिक्री की शर्त के रूप में यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि याचिकाकर्ता का सिलेंडर ग्राहक को इस सख्त शर्त पर मुफ्त ऋण पर दिया जाएगा कि उन सिलेंडरों को याचिकाकर्ता के कारखाने में वापस कर दिया जाएगा जहां से उन्हें जारी किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता की कंपनी ग्राहकों को बेचे गए सामान पर कर वसूल रही है और इसका भुगतान कर रही है और यह रिटर्न में विधिवत परिलक्षित होता है, लेकिन आकलन अधिकारियों को 1 रुपये प्रति दिन पेल सिलेंडर के निरोध शुल्क पर बिक्री कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा ग्राहकों से वसूला जाता है जो निर्दिष्ट अवधि से अधिक सिलेंडर रखते हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि एक विशेष अवधि के बाद हिरासत में रखे गए सिलेंडर 'माल' नहीं हैं और याचिकाकर्ता द्वारा चार्ज की गई निरोध राशि को याचिकाकर्ता के कुल "टर्नओवर" में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि इसे बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। संशोधित अधिनियम की संवैधानिक वैधता के बारे में अन्य तर्क प्रकृति में समान हैं; लिखित बयान में उन सभी आरोपों का खंडन किया गया है। हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है। हमें इसमें कोई सार नहीं मिलता है। बेशक, याचिकाकर्ता एक 'डीलर' है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2 (एफ) में "माल" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

"माल" का अर्थ है समाचार पत्रों, कार्रवाई योग्य दावों, धन, स्टॉक और शेयरों या प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति, लेकिन इसमें बढ़ती फसलें, घास, पेड़ और भूमि से जुड़ी चीजें शामिल हैं जिन्हें बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत अलग करने पर सहमति हुई है।

(16) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह अपने ग्राहकों को निर्दिष्ट अवधि से अधिक सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी को

रिफिलिंग के लिए सिलेंडर की आवश्यकता होती है और उसे "माल" नहीं कहा जा सकता है और विशेष अवधि से अधिक सिलेंडरों का प्रतिधारण 1 रुपये प्रति दिन निरोध शुल्क का उत्तरदायी है और इसे अनयोज्य दावा कहा जा सकता है जिसे "माल" शब्द से छूट दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की इस दलील में हमें कोई दम नजर नहीं आता। सिलेंडर के साथ ग्राहकों को गैस की आपूर्ति की जाती है और सिलेंडर का उपयोग करने के अधिकार की कीमत उस कुल राशि में शामिल होती है जो गैस की आपूर्ति के लिए ग्राहकों से ली जाती है जो "माल" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है जो बिक्री के अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाती है। उस अनुबंध में आगे एक शर्त निर्धारित की गई थी कि यदि सिलेंडर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किए जाते हैं, तो प्रति सिलेंडर 1 रुपये प्रति दिन का शुल्क लगाया जाएगा जो बिक्री की निरंतरता में होगा और इस प्रकार का कोई भी पैसा याचिकाकर्ता के 'टर्नओवर' में शामिल किया जाएगा क्योंकि कंटेनर के रूप में सिलेंडर के साथ गैस की बिक्री और एक विशेष अवधि के बाद सिलेंडर का प्रतिधारण "माल" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। चूंकि इसमें माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण शामिल था, इसलिए उस पर लगाए गए किसी भी शुल्क को याचिकाकर्ता के कुल 'टर्नओवर' में शामिल किया जाएगा।

**1989 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 13401।**

(17) इस मामले में, याचिकाकर्ता की कंपनी टूरिंग, टूर आयोजित करने के व्यवसाय में लगी हुई है और किसी भी कंपनी के कर्मियों के परिवहन के उद्देश्य से अपनी बसों को किराए पर लेने के लिए अनुबंध में भी प्रवेश करती है। अनुबंध पी/एल के तहत याचिकाकर्ता ने मेसर्स आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है, ताकि मेसर्स आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड के कर्मचारियों को दिल्ली/नई दिल्ली से आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड, फरीदाबाद तक सुबह और शाम को आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड से दिल्ली/नई दिल्ली ले जाने के लिए अपनी चार बसें उपलब्ध कराई जा सकें। संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को अन्य रिट याचिकाओं की तरह ही शर्तों में चुनौती दी गई है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और किसी भी सामान

का उपयोग करने के अधिकार को स्थानांतरित नहीं करते हैं और इसलिए, संशोधित परिभाषा के अनुसार भी बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। अनुबंध पी/एल के अवलोकन से पता चलता है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वाहन का प्रभावी या सामान्य नियंत्रण आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड के पास है, हालांकि मालिक को एक ड्राइवर और एक कंडक्टर प्रदान करना होगा और आवश्यक मरम्मत करनी होगी। हमें नहीं लगता है, यह माना जा सकता है कि समझौते को निष्पादित करने के बाद वाहन का प्रभावी नियंत्रण उसके मालिक के पास रहता है। आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड द्वारा अपनी कस्टडी से अलग बसों के कब्जे का अधिग्रहण किया गया है और जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, बसों के कब्जे का हस्तांतरण होता है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता द्वारा अधिकार का अधिग्रहण किया जाता है और हस्तांतरणकर्ता द्वारा इसे खो दिया जाता है। अनुबंध पी/एल के विभिन्न खंडों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बसों का प्रभावी कब्जा और नियंत्रण ग्राहकों को जाता है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यह शब्द के विस्तारित अर्थ के भीतर 'बिक्री' का मामला है क्योंकि मूल्यवान प्रतिफल के लिए वाहन का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया गया था और बिक्री-कर अपरिहार्य है।

(18) कुछ मामलों में, याचिकाकर्ताओं ने आकलन अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन तैयार करने के बाद रिट याचिकाएं दायर की हैं, जबकि अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के कारण कुछ मामलों में अपील दायर नहीं की गई है। यह न्याय के हित में होगा यदि उन याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ अपील दायर नहीं की है, उन्हें एक महीने की अवधि के भीतर इसे दायर करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने पहले अपील दायर नहीं की थी, वे इस तारीख से एक महीने के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

(19) ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**आर.एन.आर.**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रशमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा

**8178-HC-सरकार यू.टी., सी.एच.डी.**

**[1] ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 560.**

